हरियाणा रोडवेज की हड़ताल, सरकार की खड़ताल, यात्री बेहाल

फ़रीदाबाद (म.मो.) इसी एक वर्ष में रोडवेज कर्मचारियों की यह चौथी हड़ताल है। इस से पहले, झूठ बोलने में माहिर भारतीय झूठा पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों की मांगे मानने का आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करवाई थी। कर्मचारी संगठन इस सरकारी धोखे को समझने में असफ़ल रहे। उधर सरकार भीतरी तौर पर कर्मचारियों को सबक सिखाने व पूरी परिवहन व्यवस्था को बेच खाने की योजना बनाती रही। तमाम सड़कें टोल कम्पनियों के हाथों बेचने के बाद पूरी परिवहन व्यवस्था बेचना इस भाजपा सरकार का एजेंडा शुरू से ही रहा है।

कर्मचारियों की तमाम न्यायोचित मांगे मान कर परिवहन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने की बजाय सरकार ऐसी खड़ताल कर रही है जिससे मामला दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। जनता के पैसे पर मौज उड़ा रहे शासक वर्ग की सेहत पर बेशक इस हड़ताल का कोई असर न पड़ता हो क्योंकि उनके पास जनता के पैसे से चलने वाली कारें हैं, परन्तु जनता जरूर त्राहि-त्राहि कर रही है। सरकार की 4000 से अधिक बसों से प्रति-दिन लाखों यात्री अपनी यात्रा पूरी करते थे। बसों में सफ़र करना इतना भी सस्ता नहीं कि लोग शैकिया तौर पर सैर-तफ़रीह के लिये इनमें यात्रा करें। केवल मजबूरी में ही लोग यात्रा करने का साहस जुटाते हैं। इससे समझा जा सकता है कि हड़ताल से यात्री कितने हलकान हो रहे हैं। जो यात्रा को जैसे-तैसे पूरी कर भी रहे हैं वह बहुत महंगे दामों पड़ रही है।

आमतौर पर जनता अपनी इस तरह की मुसीबत के लिये सीधे-सीधे कर्मचारियों को ही दोषी ठहराती है जबकि सारी कारस्तानी पर्दे के पीछे बैठी सरकार कर रही है। सुधी पाठकों ने 'मज़दूर मोर्चा' के पिछले कई अंकों में पढा होगा कि मोटी व नकद कमाई वाले इस महकमे को सरकार कैसे बर्बाद करने पर तुली हुई है। अच्छी भली बसें खड़ी हैं परन्तु चलाने वाले ड्राइवर कंडक्टर नहीं हैं। बस बिगड़ गयी तो समारने वाले मिस्त्री नहीं हैं। मोटे कमीशन के चक्कर में नकली एवं घटिया स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाते हैं। अपनी मूर्खताओं, लालच व भ्रष्टाचार की भरपाई करने के लिये सरकार को कुछ नज़र आता है तो कर्मचारी। कम कर्मचारियों से अधिक काम लिया जाय। पूरे वेतन पर नियमित कर्मचारी भर्ती करने की बजाय ठेके आदि पर कच्चे कर्मचारी भर्ती किये जायें। पचास लाख की बस को किसी भी राह चलते कच्चे कर्मचारी के हाथों से बर्बाद करने में सरकार को कोई संकोच नहीं लेकिन नियमित कर्मचारी नहीं रखना।

एक ऑटो रिक्शा चालक किराये पर ऑटो लेकर सड़क पर चलने की तमाम फ़टीकें भुगतने व किराया निकालने के बावजूद शाम को हज़ार रुपये घर लेकर जाता है। बसें चलाने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट कम्पनियां नेताओं के मोटे चंदे व अफ़सरों को मोटी रिश्वतें देने के बावजूद मोटा मुनाफ़ा कमा रही हैं। इसी मोटे मुनाफ़े को देखते हुये ही सरकार ने इस व्यापार/सेवा को अपने हाथों में लिया था। परन्तु आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार व उसकी मशीनरी ने इसे घाटे का कारोबार बना दिया। रोडवेज ही क्या, सरकारी हाथों में चलती रेल व हवाई कम्पनी (एयर इन्डिया) भी मुनाफ़े की जगह भारी घाटा कमाती हैं। अकेले हरियाणा नहीं, पंजाब व राजस्थान रोडवेज सहित अधिकांश राज्यों की यही स्थिति है। वास्तव में भ्रष्ट शासन वर्ग द्वारा यह स्थिति बनाई जाती है। फ़िर उसके लिये कर्मचारियों को दोषी बता कर सरकारी उपक्रम को निजी हाथों बेच कर मोटा माल डकारा जाता है। इसी को तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम।

जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने का नाटक करते हुये खट्टर सरकार हड़ताल के बावजूद बसों को चलाने का प्रयास करती नज़र आ रही है। जो परिवहन व्यवस्था हड़ताल से पूर्व भी प्रशासकी निकम्मेपन के चलते सुचारु रूप से नहीं चल पा रही थी, वह भला हड़ताल के दौरान कैसे सुचारु ठीक हो सकती है? अपनी मूर्खता का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुये बसों को डिपुओं की बजाय पुलिस लाइनों में खड़ा करके वहां से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ड्राइवरी पुलिस के सिपाही व अन्य महकमों के ड्राइवरों से कराई जाने की योजना है। विदित है कि अन्य महकमों के ड्राइवर कार व जीप आदि के ही ड्राइवर होते हैं न कि बसों के। इतना ही नही अनेकों महकमे तो अपने ड्राइवरों के अभाव में खुद रोडवेज पर ही निर्भर रहते हैं।

दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या पुलिस में सिपाही फ़ाल्तू हैं जो वे हज़ारों की संख्या में बसें चलाने के लिये उपलब्ध होंगे? सर्वविदित है कि पुलिस विभाग पहले से ही सिपाहियों की कमी से जूझ रहा है। दूसरी ओर अन्य महकमों के ड्राइवर बसों पर लगाने के बाद उनकी गाड़ियां कैसे चलेंगी? इसके अलावा क्या बसें केवल ड्राइवरों से ही चल पायेंगी, कंडक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? हां, बिना कंडक्टर के भी यानी टिकट काटे बिना चलाई जा सकती हैं जैसे रक्षाबंधन के दिन। परन्तु बिना टिकट काटे कितने दिन तक फ्री सेवा दी जा सकती है?

मामला केवल रोडवेज कर्मचारियों का नहीं रह गया है, आज शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो स्वास्थ्यकर्मी अपनी। नौकरी के लिये हर प्रकार से चयनित हो चुके हज़ारों शिक्षक पंचकुला में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है नियुक्ति पत्र। सवाल बड़ा वाजिब है जब चयन हो गया तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिये जा रहे? दूसरी ओर एक समाचार यह भी आ रहा है कि राज्य भर के 2200 कच्चे कम्प्यूटर टीचरों ने संघर्ष का रास्ता त्याग कर 'लेन-देन' का रास्ता पकड़ा है। उन्होंने पक्का होने के लिये पांच-पांच हज़ार प्रति व्यक्ति के हिसाब से एकत्र कर लिया है। जानकार बताते हैं कि शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा के कुछ प्यादों ने यह सौदा तय किया है।

एनआईटी के विधायक नगेन्द्र भड़ाना शिव टूल्स एंड इंजीनियरिंग के मालिक भीकम सिंह बघेल को अपने घर पर चाय पान कराते हुए। विदित है कि इसी कम्पनी में श्रमिक माया का बांया हाथ कटा था और इन्हीं विधायक महोदय ने माया को धोखे में रख कर एक नकली समझौता कराया था जिससे मालिक अब मुकुर गया है। इन्हीं विधायक के राजनीतिक प्रभाव के चलते न तो श्रमिक विभाग माया के साथ न्याय कर रहा है न ही पुलिस कोई सुनवाई कर रही है।

खुंखार अजय गूजर की गिरफ़्तारी पर खुश होने की जरूरत नहीं

शिक्षा एवं रोजगार के अभाव में नित्य पैदा हो रहे हैं खुंखार अपराधी

फ़रीदाबाद (म.मो) इसी सप्ताह, अनेकों हत्याओं व अन्य जघन्य अपराधों में 10 वर्ष से वांछित खुंखार अपराधी अजय गूजर को पलवल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उस पर 50 हज़ार का इनाम भी घोषित था। जाहिर है इससे पुलिस को अपनी पीठ थपथपाने का एक उचित अवसर मिल गया। इससे कुछ माह पूर्व फ़रीदाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में एक दुर्दान्त अपराधी को मार गिराने का जश्न मनाया था। उसके कुछ समय बाद उसके एक साथी की पलवल पुलिस की हिरासत में मौत हो गयी थी। लेकिन इस सबके बावजूद न तो अपराधिक वारदातों में कोई कमी हो रही है न अपराधियों की संख्या में।

दिन दूणे रात चौगुणे बढते अपराधों के लिये जनता एवं समाज पुलिस को दोषी ठहराता है। पुलिस को निकम्मी व भ्रष्ट बता कर कोसता है। बेशक इन आरोपों में भी काफ़ी हद तक सच्चाई हो सकती है लेकिन समाज में बढते अपराध का कारण पुलिस नहीं हो सकती। इसके लिये वह सामाजिक एवं राजकीय व्यवस्था है जिसमें शिक्षा से आम जनता को वंचित किया जा रहा है। सरकारी स्कूल, कॉलेजों व युनिवर्सिटियों में बड़े ही संगठित तरीके से शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है। हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में तीस-चालीस हज़ार शिक्षकों के पद रिक्त हो जाना, स्कूल और कॉलेज बिना प्रधान आचार्यों के चलाना युनिवर्सिटियों में घटिया से घटिया एवं भ्रष्टतम चापलूसों को वीसी नियुक्त करना आदि, पूरी शिक्षा व्यवस्था को उजाड़ने के लिये पर्याप्त हैं।

बीते दो वर्षों में हरियाणा सरकार ने करीब एक हज़ार छोटे-बड़े स्कूल यह कह कर बंद कर दिये कि उनमें पढने वाले बच्चे ही पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहे। जब स्कूल में पढाने वाला ही कोई न हो, बैठने तक का उचित स्थान न हो, पीने का पानी व शौचालय तक न हो तो बच्चे क्या वहां अपनी ऐसी-तैसी कराने को आयेंगे। निकम्मी सरकार ने स्कूलों की स्थिति सुधार कर बच्चों को आकृष्ट करने की अपेक्षा स्कूलों को ही बंद करना उचित समझा। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को कॉलेज में बतौर प्रोफ़ेसर लगाया जा रहा है चपरासी से भी कम वेतन पर। जी हां सरकारी कॉलेज़ों के तमाम चपरासी 30-40 हज़ार वेतन पाते हैं जबकि बड़ी संख्या में तैनात अतिथि प्रोफ़ेसर 15 से 25 हज़ार में रखे जा रहे हैं।

लगभग यही हालत आईटीआई, पॉलीटेक्निक व इन्जीनियरिंग कॉलेजों की है। राज्य में कुकरमुत्तों की तरह खुले इन्जीनियरिंग कॉलेजों में बिना उचित पढाई के छात्रों को महंगे दामों डिग्रियां तो बेच दी लेकिन उन्हें आता-जाता कुछ नहीं, लिहाजा रोज़गार के बाजार में वे पिट गये। इसके चलते फ़रीदाबाद में खुले दर्जनों ऐसे कॉलेज अब छात्रों की प्रतीक्षा में मक्खियां मार रहे हैं।

शिक्षा, विशेषकर पेशेवर शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे युवा यदि सही ढंग से लैस हो जाय तो वह कुछ अच्छे ढंग से कमाने-खाने लायक बन सकता है। केरल उसका बेहतरीन उदाहरण है। वहां का युवा वर्ग शिक्षा तथा पेशेवर शिक्षा एवं ट्रेनिंग के बल पर न केवल पूरे भारत में बल्कि दुनिया भर में, बिना किसी मन्त्री की सिफ़ारिश के रोजगार पा लेता है। इसके बरक्स हरियाणा का युवा शिक्षा के अभाव में 'मरता क्या न करता' की तर्ज पर अपराध जगत की ओर अग्रसर होने लगता है। समाज में एक ओर बढती अमीरी और दूसरी ओर बढ़ती ग़रीबी के हालात में जब उसे टीवी और सिनेमा में जिंदगी की रंगीनियां परोसी जाती है तो उसका मन भटकता है। वह वे सब रंगीनियां भोगने को लालायित होता है। ऐसे में उसे अपराधी गैंग अपने गिरोह में भर्ती कर लेते हैं। अकेले हरियाणा व दिल्ली में आज ऐसे सैंकड़ों खुंखार अपराधी गैंग हैं जिनके पास सैंकड़ों की संख्या में 14 से 30 साल तक के युवा सदस्य हैं। ये सभी लोग अपराध की दुनिया में इतने गहरे उतर चुके हैं कि वापस लौटने के बारे में सोच भी नहीं सकते।

नीमका जेल यात्रा के दौरान इस संवाददाता को ऐसे दर्जनों जघन्य अपराधियों के व्यवहार एवं समझ का अध्ययन करने का मौका मिला जो निहायत ग़रीब घरों से थे। उनके पिछड़े ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। ग़रीबी के चलते स्कूल जाने की उम्र में छोटे-मोटे काम-धंधे करने लगे। कोई ट्रकों पर क्लीनरी करने लगा तो कोई ढाबों पर। इसी दौरान वे आपराधिक गिरोहों के सम्पर्क में आये। बातचीत में वे बताते थे कि वे सिवाय चोरी, लूट-मार, डकैती, अफ़ीम गांजा आदि का धंधा करने के अलावा कुछ करना जानते ही नहीं। कुछेक तो भाड़े पर हत्या तक करने का काम करते थे। लगभग सभी का कहना था कि जेल से छूटने के बाद भी यही सब आपराधिक धंधे ही करेंगे क्योंकि इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ और आता भी तो नहीं।

पर्याप्त मात्रा में शिक्षण एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अपेक्षा पुलिस थानों, अदालतों व जेलों की संख्या बढाने में जुटी है। शिक्षण-प्रशिक्षण के बजट को पुलिस, न्यायपालिका व जेलों पर बर्बाद कर रही है। पहले जहां एक थाना था वहां अब चार हैं, पहले जहां चार अदालत थीं वहां अब 40 हैं, पहले जहां 250 कैदियों की जेल थी वहां अब 2500 कैदियों की जेल है। इसके बावजूद भी काबू कुछ नहीं आ रहा। सब कुछ अस्त-व्यस्त है।

पुलिस एवं आपराधिक न्याय व्यवस्था सही सलामत चल रहे समाज में इक्का-दुक्का भटके नागरिकों को अपराध करने पर पकड़ सकती है; परन्तु जब इतने बड़े पैमाने पर अपराधियों की पौध तैयार हो रही हो तो कोई भी पुलिस एवं आपराधिक न्याय व्यवस्था इससे निपटने में सक्षम हो नहीं सकती। हां यदा-कदा इक्का-दुक्का अपराधी को पकड़ कर अपनी पीठ ज़रूर थपथपा सकती है।